The Tribune- 01- January-2022

TRAINING ON JAL JEEVAN MISSION

Kaithal: A four-day L-3 training programme under the Jal Jeevan Mission which was organised by the Resource Centre Green Earth Organisation, Kurukshetra, under the aegis of Ministry of Jal Shakti, Government of India, concluded at Kaithal on Friday. Programme coordinators Monika Bhardwaj and Sushil Kumar said in the programme, members of village water and sewerage committees of 30 villages and other stakeholders were trained in collaboration with the Public Health Engineering Department and Water and Sanitation Support Organisation, Panchkula. Ashok Khanduja, Superintendent Engineer Public Health Engineering, Kaithal Circle, attended the closing session as the chief guest.

Orissa Post- 01- January-2022

Centre releases ₹830cr under Jal Jeevan Mission

The Centre has put emphasis on tap water connection to every household in the rural areas across the country under Jal Jeevan Mission

Odisha has constituted 3,695 village water and sanitation committees and developed 2,345 village action plans for implementation of the scheme

POST NEWS NETWORK

New Delhi, Dec 31: The Centre Friday released Rs 830.85 crore to Odisha to expedite the implementation of Jal Jeevan Mission in the state.

According to the Union Jal Shakti Ministry, Odisha plans to become 'Har Ghar Jal' state in 2024.

"Out of 85.67 lakh rural households in Odisha, 35.37 lakh (41.28 per cent) households have tap water supply. The work is going on at full pace to ensure water supply in villages. Efforts are being made to ensure 100 per cent tap water connectivity in rural areas," the ministry said.

The Centre has put emphasis on tap water connection to every household in the rural areas across the country under the Jal Jeevan Mission.

"There is a significant rise in budgetary allocation for Odisha from Rs 812.15 crore in the previous fiscal to Rs 3,323.42 crore in 2021-22 financial year," the ministry said.

In order to implement the Jal Jeevan Mission, the coastal state has constituted 3,695 village water and sanitation committees and developed 2,345 village action plans, said the ministry.

"Six implementing support agencies (ISAs) have been engaged in Odisha to create awareness on the mission, sensitise the village community on the importance of safe water and extend support to Panchayati Raj Institutions (PRIs) for implementation of the scheme.

"As many as 17,756 women have been trained to conduct water quality testing using field test kits in Odisha while the state has 77 water testing laboratories," said the ministry.

Till date, 36,372 schools (67 per cent) and 29,097 Aanganwadi Centres (54 per cent) in Odisha have been provided with tap water supply, the ministry stated further.

Jansatta- 01- January-2022

'गंगा संरक्षण से जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी'

नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि गंगा जल के संरक्षण और इसकी निर्मलता सुनिश्चित कर, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा और सुंदरवन की जीवंतता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

मिश्रा ने बताया कि मिट्टी के कटाव एवं उसे समुद्र में बहकर जाने से रोकने तथा भूजल को पेयजल एवं सिंचाई योग्य बनाए रखने के लिए हर समय नदी में न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह बनाए रखना जरूरी है। एनएमसीजी के महानिदेशक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने से उर्वर भूमि में खारा जल जाकर उसे प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा दुनिया में शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में भूजल के दोहन से मिट्टी और भूजल में खारापन बढ़ता है।

Swadesh Bhopal- 01- January-2022

पेयजल आपूर्ति योजना में प्रदेश को मिला 15381.72 करोड़ का आवंटन

■ जल जीवन मिशन में 22 मेगा पेयजल योजनाओं से 2023 तक हर घर जल उपलब्ध कराने की है राज्य की योजना

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में पेयजल आपूर्ति योजनाओं हेतु राज्य स्तरीय योजना समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में 15381.72 करोड़ रूपये स्वीकृत दी गयी। 1.09 करोड़ से अधिक ग्रामीण आबादी को नल जल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 22 बहु ग्राम योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इन 22 योजनाओं के माध्यम से रीवा, सतना, सीहोर, सीधी, अलीराजपुर, पन्ना, मंडला, सागर, कटनी, धार, श्योपुर, उमरिया और खरगौन जिले के 9240 गांवों को लाभ मिलेगा। चूंकि मध्य प्रदेश साल 2023 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है ऐसे में इन योजनाओं की स्वीकृति और महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सभी गांवों में गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। अनुमान है कि 9,240 लाख गांवों में रहने वाले 22 लाख से अधिक परिवारों को अगले 30-40 सालों तक नियमित रूप से पर्याप्त स्वच्छ जल मुहैया कराया जा सकेगा।

राज्य को मिले हैं 5117 करोड़

जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के लिए योजनाओं पर विचार एवं अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय योजना समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान किया गया है। एसएलएसएससी जल आपूर्ति योजनाओं /परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक नामांकित व्यक्ति समिति का सदस्य होता है। साल 2021-22 में राज्य को 5,117 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी जिसमें से 2558 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश में हर घर जल कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है। इन योजनाओं से उन महिलाओं और बच्चों के कठिन परिश्रम में कमी आयेगी जो दूर स्थित जल स्रोतों से पानी लाने में अपना कई घंटे बर्बाद करते हैं।

Dainik Bharat- 01- January-2022

झारखंड के लिए 9,544 करोड़ की 315 जलापूर्ति योजनाएं मंजूर

31/12/2021

नई दिल्ली। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड के लिए 9,544 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजनाओं की मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य के 4,424 गांवों में 7.97 लाख परिवारों को लाभांवित करने के लिए 315 जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई है। इस राशि से झारखंड को वर्ष, 2024 तक 'हर घर जल' वाला राज्य बनने की योजना है।

झारखंड के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 9,544 करोड़ रुपए की 315 जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गईं हैं। इन योजनाओं से राज्य के 4,424 गांवों में लगभग 8 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी।

जानकारी हो कि 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय झारखंड में केवल 3.45 लाख (5.83 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। 28 महीनों में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की बाधाओं के बावजूद राज्य ने 6.73 लाख (11.38 प्रतिशत) घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया है। अभी तक राज्य के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों में से 10.18 लाख (17.20 प्रतिशत) परिवारों को उनके घरों में नल का पानी मिल रहा है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए की जाने वाली योजनाओं पर विचार और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) के गठन का प्रावधान है। एसएलएसएससी जल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं पर विचार करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) का एक नामांकित व्यक्ति समिति का सदस्य होता है।

झारखंड को अब तक 512.22 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'हर घर जल' कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य में समान वित्तीय प्रगति के साथ मिशन कार्यों की वास्तविक प्रगति के साथ, राज्य को आगे की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उनके घरों में नल का पानी मिले।

इसके अलावा, 2021-22 में झारखंड को 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिए अनुदान दिया है। अगले पांच वर्ष यानी 2025-26 तक के लिए 3,952 करोड़ रुपए का सुनिश्चित वित्त-पोषण उपलब्ध है।